

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश



“प्रेम निर्णय का अभाव है”

तिब्बत देश

अगस्त, 2025, वर्ष : 46 अंक : 8

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार
पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित
तिब्बत के बारे में सही जानकारी के
साथ हर महीने आपके हाथों में



सिक्कियों ने तिब्बत और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और प्राकृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जिसमें उनके स्थायी धार्मिक संबंध भी शामिल हैं।

समाचार -

समाचार -

1. लेह स्थित लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख गोंपा संघ की दीर्घायु प्रार्थना में शामिल हुए परम पावन दलाई लामा 2
2. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत की 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 3
3. डिप्टी स्पीकर डोलमा शेरिंग तेखांग ने फिल्म 'शोले' की 50वीं वर्षगांठ पर गीत विमोचन समारोह में भाग लिया 4
4. शिक्षा मंत्री थरलम डोलमा चांगरा ने जर्मनी के 'इनिशिएटिव ओबरलैंड' के प्रतिनिधिमंडल के साथ संभूत मुख्यालय और पेटियन स्कूल का दौरा किया 4
5. प्रेस विज्ञप्ति: तिब्बती चुनाव आयोग ने 2026 के आम चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया 5
6. लुधियाना के तिब्बती व्यापारी संघ ने परम पावन दलाई लामा के सम्मान में 'करुणा वर्ष' और भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 6
7. . करुणा वर्ष में तिब्बती और कन्नड़ समुदाय द्वारा याद किए गए स्वर्गीय मुख्यमंत्री एस निजलिगप्पा 7
8. कुल्लू-मनाली के तिब्बती समुदाय ने 'करुणा वर्ष' में पर्यावरण सफाई अभियान शुरू किया 8
9. चीन ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह के दौरान तिब्बतियों को सामूहिक हिरासत में लिया 8
10. तिब्बत की नदी पर जल-युद्ध तेज करने की चीनी रणनीति 10
12. अमेरिकी विदेश विभाग ने तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति को गंभीर बताया 12
13. चीनी दुर्व्यवहार के बाद होटल से कूदने वाली कैदी तिब्बती उद्यमी की बहन गंभीर 14
14. तिब्बत के भिक्षु शेरसांग ग्यात्सो ने चीनी दमन के विरोध में सांग मठ में आत्महत्या की 15
15. तिब्बती राजनीतिक बंदी का परिचय 16

प्रधान संपादक

ताशी देकि

सलाहकार संपादक

प्रो. श्यामनाथ मिश्र, डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक

मिगमार छमचो

वितरण प्रबंधक

नावांग छोडेन

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :

भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र

एच - 10 लाजपत नगर - 3

नई दिल्ली - 110024, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचारों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें।

मुद्रक एवं प्रकाशक

जमयांग दोरजी द्वारा

नोरबू ग्राफिक्स, 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार, लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित
जानकारी के लिए भारत -
तिब्बत समन्वय केन्द्र की
वेबसाइट

coordinator@india
tibet.net



प्रो० श्यामनाथ मिश्र

श्री श्याम मंदिर, खेतड़ी

जिला—झुंझुनू (राजस्थान)

मो.—9079352370

E-mail:- shyamnathji@gmail.com

तिब्बती समुदाय द्वारा 15 अगस्त, 2025 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रम किये गये। इससे स्पष्ट है कि तिब्बती भारतवासी होने के साथ ही भारतीय भी हैं। वे भारत के अनेक उत्सवों, आयोजनों, पर्व—त्योहारों, तीर्थों, धार्मिक स्थलों आदि के प्रति सदैव श्रद्धा प्रकट करते हैं। उनमें शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं, तथा उनकी समृद्धि एवं प्रगति में आगे रहते हैं।

तिब्बती घरणार्थी व्यापारी संघ द्वारा पंजाब के लुधियाना में आयोजित 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बत सरकार के राजप्रमुख एवं शासन प्रमुख सिक्खोंग पेंपा त्सेरिंग, तिब्बती संसद के उपसभापति तथा दो तिब्बती न्याय आयुक्त शामिल थे। तिब्बतियों को पूरा विश्वास है कि भारत की तरह तिब्बत भी अवश्य स्वतंत्र होगा। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हैं। भारतीय आजादी की लड़ाई में दो तरह की धारारें समान रूप से महत्वपूर्ण थीं। एक धारा में गरम विचार वाले थे, जैसे—चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सावरकर, उधमसिंह आदि। वे मानते थे कि अंग्रेजों से आजादी छिननी होगी। इस विचार के अनेक लोग देश के लिये बलिदान हो गये। ब्रिटिश सरकार ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उग्रवादी—आतं. कवादी कहती थी।

दूसरी धारा सत्य—अहिंसा की थी। इसमें गांधी—नेहरू आदि शामिल थे। इनका मत था कि अंग्रेजों का हृदय बदलने से भारत आजाद होगा। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा या बल—प्रयोग अनुचित है। उसे अच्छी तरह अहिंसक तरीके से समझाना—बुझाना चाहिये। तभी ब्रिटिश सरकार हमारी मांग मानकर भारत को आजाद करेगी। उदारवादी आंदोलनकारियों ने सदैव गरम विचार वालों को अपने से दूर रखा तथा उनकी कभी कोई मदद नहीं की। तिब्बती संघर्ष इसी विचारधारा से प्रेरित—प्रभावित है। तिब्बती धर्मगुरु परम्पावन दलाई लामा ने इसी जुलाई—अगस्त, 2025 में लद्दाख क्षेत्र के कई स्थानों पर अपने प्रवचन एवं उपदेश में शांति—अहिंसा को महत्वपूर्ण बताया है। अपनी 90वीं वर्षगांठ पूर्ण कर चुके दलाई लामा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये वर्तमान वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

तिब्बती संघर्ष का समाधान क्या हो? तिब्बत समर्थक कहते हैं कि साम्राज्यवादी चीन सरकार ने स्वतंत्र तिब्बत देश पर कब्जा किया था। उस समय के तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज, मुद्रा, पासपोर्ट—विजा, डाक टिकिट तथा सेना इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार 1947 में दिल्ली में आयोजित एषियाई संबंध सम्मेलन में, जिसे अहिंसा के पुजारी गांधी ने संबोधित किया था, स्वतंत्र तिब्बत देश के दो प्रतिनिधि आये थे। बीजिंग में चीन सरकार ने 23 मई, 1951 को स्वतंत्र तिब्बत के साथ

सत्रह सूत्री समझौते किये थे। स्पष्ट है कि तिब्बत पर अवैध कब्जा करके चीन ने उसे अपना भूभाग बता—बना दिया है।

अन्य राय है मध्यममार्ग अर्थात् वास्तविक स्वायत्तता की। तिब्बती समुदाय का मत है कि तिब्बत के साजिषपूर्ण चीनीकरण से तिब्बती पहचान खतरे में है। वहाँ मौलिक अधिकार सहित सभी प्रकार के अधिकारों से तिब्बती लोग वंचित हैं। क्रूरतापूर्ण दमन से सारे तिब्बती त्रस्त हैं। एक लोककल्याणकारी तिब्बती कार्यकर्ता को गत आठ माह से चीनी प्रशासन ने गिरफ्तार कर रखा है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तिब्बती महिला ने ऊँची बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या की असफल कोषि की। उसके भाई को चीनी प्रशासन ने हिरासत में रखा है तथा उससे वकीलों एवं परिजनों के मिलने पर पाबंदी है। ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में वास्तविक स्वायत्तता ही व्यावहारिक समाधान है। संविधान तथा राष्ट्रीयता कानून के अनुकूल चीन सरकार अपने पास अंतरराष्ट्रीय विषय एवं प्रतिरक्षा रखे तथा पेश विषयों, जैसे—कृषि, शिक्षा, पर्यटन आदि पर कानून बनाने का अधिकार तिब्बतियों को प्रदान करे। सम्पूर्ण तिब्बती भौगोलिक क्षेत्र को स्वायत्त किया जाये। अभी चीन सरकार ने तिब्बती भौगोलिक क्षेत्र को पूर्णतः विकृत कर चीनी प्रदेशों में मिला रखा है।

तिब्बती समुदाय के समान तिब्बत समर्थक भी अब पूर्ण आजादी की मांग को छोड़कर वास्तविक स्वायत्तता के पक्ष में हो गये हैं। सभी मान रहे हैं कि तिब्बत की स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक है तिब्बती पहचान की सुरक्षा। इसके अभाव में तिब्बती मानसिक रूप से गुलाम हो जायेंगे। भारत ऐसी ही मानसिक गुलामी का पिकार है जहाँ आजादी मिलने के बाद भी भारत के कई लोग एवं संस्थान अनेक मुगलकालीन एवं ब्रिटिशकालीन प्रतीकों, मूर्तियों और नामों आदि को बदलने के प्रयासों का विरोध करते हैं।

सिक्खोंग पेंपा त्सेरिंग हिमाचल प्रदेश एवं अन्य भारतीय प्रांतों में स्थित तिब्बती आवासों में जाकर संपूर्ण तिब्बती समुदाय, विशेषकर युवापीढ़ी को अधिकाधिक जागरूक कर रहे हैं। दायित्व संभालने लायक युवापीढ़ी को बनाना वर्तमान पीढ़ी का महत्वपूर्ण दायित्व है। तिब्बत की वर्तमान दमनपूर्ण आंतरिक स्थिति के साथ तिब्बतियों को निर्वासित तिब्बत सरकार के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जा रही है।

वर्तमान सन्दर्भ में उत्तराखंड में बागेश्वर के तिब्बत समर्थक, चिंतक एवं प्रमुख कार्यकर्ता रतनसिंह किरमोलिया का विचार है कि दलाई लामा को राष्ट्रीय—अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार—सम्मान एवं उपाधि देना बहुत उचित है। इसके साथ ही विस्तारवादी चीन सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना भी आवश्यक है तभी उपनिवेशवादी चीन सरकार मानवीय मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों तथा राष्ट्रीय—अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तिब्बत समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिये बाध्य होगी। विषय जनमत तिब्बत के पक्ष में है। इसे सक्रिय सहयोग एवं समर्थन से आगे बढ़कर परिणाम तक पहुँचना होगा। यह समस्त विषय के, यहाँ तक कि तिब्बत के साथ—साथ चीन के भी हित में होगा।

◆ 1. लेह स्थित लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख गोंपा संघ की दीर्घायु प्रार्थना में शामिल हुए परम पावन दलाई लामा

१७ अगस्त, २०२५

-dalailama.com

शेवासेल/ लेह (लद्दाख)। शिवात्सेल फोडरंग से सटे कालचक्र शिक्षण स्थल पर आज दूसरे दिन यानी १७ अगस्त को भी लगभग ५०,००० लोग चिलचिलाती धूप में एकत्र हुए। ये यहां पर परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने आए हैं। परम पावन अपने निवास से मैदान के दूर स्थित शिक्षण मंडप तक गोल्फ कार्ट से गए, उस समय पारंपरिक लद्दाखी ढोल और बैड बाजा से उनका स्वागत किया। इस समारोह का आयोजन और प्रस्तुतिकरण लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) और लद्दाख गोंपा संघ (एलजीए) द्वारा किया गया था।

गोल्फ कार्ट से उतरकर मंडप में पहुंच कर परम पावन ने सबसे पहले सिंहासन के पीछे स्थित बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया। इसके बाद थिक्से रिनपोछे उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। आसन ग्रहण करने से पहले परम पावन मंच के सामने आए और भीड़ पर एक नजर डाली और उनका अभिवादन किया।

परम पावन की दीर्घायु प्रार्थना की शुरुआत 'तीन सातव्यों की प्रार्थना' से हुई। इसके बाद प्रसाद में में खीर और चाय परोसे गए। तत्पश्चात, बुद्ध और बोधिसत्वों का आह्वान किया गया और उन्हें स्नान कराया गया। उनके प्रति एक श्लोक का मंडल अर्पण किया गया।

परम पावन की दीर्घायु-प्रार्थना का अनुष्ठान 'सोलह अर्हतों की प्रार्थना' पर आधारित था, जो बुद्ध के मुक्त अनुयायी हैं, और जिन्होंने उनके प्रवचनों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। इसके बाद सप्तांग अर्पण किया गया। सोग अर्पण किया गया और परम पावन ने उसका एक भाग ग्रहण किया।

इसके बाद एलबीए और एलजीए के प्रतिनिधियों ने परम पावन को श्रद्धांजलि अर्पित की। थिक्से रिनपोछे ने एक मंडल अर्पण किया और उन्हें बुद्ध के शरीर, वाणी और मन के प्रतीक, मठवासी वस्त्र, फलों से भरा एक भिक्षापात्र और एक भिक्षु-दंड भेंट किया। परम पावन ने सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वस्तु को अपने माथे से लगाया। आठ शुभ प्रतीकों, सात राजसी प्रतीकों और आठ शुभ द्रव्यों के प्रतीक थालियां परम पावन के जीवन की दीर्घायु की कामना के साथ अर्पित की गईं।

जब स्थानीय लोगों का एक विशाल जुलूस मंच के सामने से गुजरा, तो परम पावन के दो शिक्षकों द्वारा रचित 'परम पावन दलाई लामा की अमरता का गीत गाया गया। प्रार्थना इस प्रकार है:

हम अगाध भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं
कि तेनजिन ग्यात्सो, हिम की महान भूमि के रक्षक,
युगों-युगों तक जीवित रहें।

आप उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं

कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों।

इसके बाद परम पावन ने सभा में एकत्रित अनुयायियों को संबोधित किया:

‘मेरे प्रिय धर्मबंधुओं और बहनों, मैं यह कहना चाहता हूं कि लद्दाख के स्थानीय और दूसरी जगहों से आए, मठवासी और सामान्य लोग मेरी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने हेतु उत्कट भक्ति के साथ यहां एकत्रित हुए हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा का पालन करनेवाले तिब्बती और हिमालयी क्षेत्र के लोग यहां विशेष रूप से मेरी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने हेतु एकत्रित हुए हैं।

‘जहां तक मेरा मामला है, मेरा जन्म तिब्बत के अमदो प्रांत के धोमे में हुआ और इसके बाद मैं मध्य तिब्बत में आ गया। तिब्बत के सभी लोगों और देवताओं ने मुझ पर दृढ़ विश्वास किया है। इसलिए, मैं तिब्बत के लोगों और देवताओं की सेवा करने का दायित्व निभा रहा हूं। मैंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन जिया है और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना भी किया है।’

इसी समय, अर्पण जुलूस के अंत में पहुंचे एक बुजुर्ग आशीर्वाद लेने के लिए आये तो परम पावन जोर से हंस पड़े, क्योंकि उन्होंने एक के ऊपर एक दो टोपियां पहन रखी थीं। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे एक तिब्बती व्यक्ति और थे, जो तिब्बती ध्वज लिए हुए थे, जिसे उन्होंने परम पावन को भेंट किया।

परम पावन ने आगे कहा, ‘तिब्बती रक्षक देवता नेचुंग चोग्याल जैसे महान धर्म राजा तिब्बती मुद्दे की सेवा के लिए कृत संकल्प हैं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। तिब्बत के रक्षक देवताओं ने नेचुंग के नेतृत्व में लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तिब्बत में मैं मुख्य रूप से पोटाला पैलेस और ग्रीष्मकालीन पैलेस नोरबुलिंगका में रहा, जहां से मैंने तिब्बती लोगों और तिब्बती परंपरा की सेवा की। मैंने तिब्बत और तिब्बती धर्म की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। पिछले वर्षों में मैंने तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के लिए अलौकिक और सांसारिक देवताओं का भी आह्वान किया है।

जहां तक मेरी बात है, मैंने बचपन से ही अपने शिक्षकों के साथ बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। मैंने संग्रहित विषयों से शुरुआत की और फिर मन और जागरूकता, तर्कशास्त्र, प्रज्ञा-सिद्धि, मध्यम मार्ग और उच्च ज्ञान (अभिधम्म) का अध्ययन किया, हालांकि कुछ पहलुओं को लेकर मैं संशय में हूं। खैर, मैंने मध्यम मार्ग के दर्शन के साथ-साथ तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा, ज्ञान की प्रकृति का भी अध्ययन किया है, जो हमारी परंपरा के उत्कृष्ट अंग हैं।

‘फिर मन के आंतरिक विज्ञान, हमारे मन और भावनाओं की कार्यप्रणाली को समझने के संबंध में आज आधुनिक वैज्ञानिक भी हमारी परंपरा से सीखने के लिए उत्सुक हैं।’

‘मैं दो दशकों से अधिक समय तक तिब्बत में रहा और कई चुनौतियों का सामना किया। बीजिंग में मेरी मुलाकात चेयरमैन माओत्से तुंग से हुई,

जहां मुझे पता चला कि हमारी विचारधाराएं और दार्शनिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। तिब्बत में हुई उथल-पुथल के कारण, मुझे अपनी मातृभूमि से भागना पड़ा और तब से मैं भारत में निर्वासन में आराम से रह रहा हूँ। मैं बुद्ध के उपदेशों के संरक्षण में योगदान दे पाया हूँ और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सलाह के लिए मुझसे संपर्क करने वाले लोगों की सेवा कर पाया हूँ। मैंने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति अर्जित की है। चाहे वे धर्म का पालन करते हों या नहीं, कई लोगों ने मेरे काम की प्रशंसा की है।'

'मेरे इतने वर्षों के जीवन में कई लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पर विश्वास किया है और मैंने उनके लिए लाभकारी होने की प्रार्थना की है। इसलिए, मैं आप सभी का ताशी देलेक / अभिवादन करना चाहता हूँ।

'मैं सांसारिक गतिविधियों या आध्यात्मिक शिक्षाओं के संदर्भ में जो कुछ भी कर पाया हूँ, आप सभी मेरी दीर्घायु के लिए ये प्रार्थनाएं करने यहां एकलित हुए हैं। जिस प्रकार आपने मेरे दीर्घायु होने की प्रार्थना की है, उसी प्रकार मैं भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करूंगा। मैं आप सभी का इन प्रार्थनाओं और अर्पण के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं सहजता से पूरी हों। धन्यवाद / ताशी देलेक।'

'ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज मुख्य भूमि चीन, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है। अतीत में वे मुझे प्रतिक्रियावादी आदि कहते थे, लेकिन मैं कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावनापूर्ण विचार नहीं रखता।'

ऐतिहासिक रूप से, सोंगसेन गम्पो के समय से ही चीन के साथ हमारे मजबूत संबंध रहे हैं। जैसे-जैसे चीनी लोग बौद्ध धर्म में रुचि लेते रहेंगे, यह स्वाभाविक रूप से फैलेगा और मुझे इस विकास में यथासंभव योगदान देने में खुशी होगी।

... इसके बाद एक संगीतमय कार्यक्रम हुआ। इसमें पहले लद्दाखी गायकों और संगीतकारों के एक समूह ने और फिर स्थानीय तिब्बती बाल ग्राम (टीसीवी) के एक समूह ने परम पावन के ९०वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गीत प्रस्तुत किए और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। टीसीवी समूह ने परम पावन के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक सौहार्दपूर्ण भाव विकसित करने की प्रतिज्ञा लेकर अपने प्रदर्शन की शुरुआत की।

जैसे ही प्रार्थनाएं समाप्त हुईं, सोलह वरिष्ठों और चारों दिशाओं के राजाओं का एक बार फिर आह्वान किया गया और उनसे प्रार्थना की गई कि लामा दीर्घायु हों और उनके उपदेश फलते-फूलते रहें। गादेन लिपा, जेत्सुन लोबसांग दोरजे रिनपोछे द्वारा परम पावन के दीर्घायु होने के अनुरोध को उनके द्वारा स्वीकार करने पर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अंतिम धन्यवाद मंडल अर्पण की गई। इसके साथ ही कई शुभ प्रार्थनाएं की गईं, जिनका समापन एक ही छंद में परम पावन की दीर्घायु-प्रार्थना के साथ हुआ।

तिब्बत के दिव्य लोक में, बर्फीले पर्वतों की शृंखला से घिरे,

प्राणियों के लिए समस्त सुख और सहायता का स्रोत
साक्षात् तेनजिन ग्यात्सो-चेनरेजिग हैं –

उनका जीवन युगों-युगों तक सुरक्षित रहे।

◆ 2. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत की ७९वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

१५ अगस्त, २०२५

धर्मशाला। भारत के स्वतंत्रता दिवस की ७९वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने गंगचेन क्वेशोंग में सामान्य एवं भव्य समारोह का आयोजन किया और भारत के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाया। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस का विषय 'नया भारत' था।



इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक आयुक्त येशी वांगमो, कार्यवाहक सिक्योंग थरलाम डोल्मा चांगरा, शिक्षा विभाग के कलोन (मंत्री), चुनाव आयुक्त लोबसांग येशी, सांसद शेरींग यांगचेन और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।

समारोह की शुरुआत कार्यवाहक सिक्योंग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उसके बाद भारतीय राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई।

अपने संबोधन में कार्यवाहक सिक्योंग थरलाम डोलमा ने निर्वासित तिब्बती लोगों और तिब्बत के भीतर रहने वाले लोगों की ओर से भारत सरकार और लोगों को हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने कहा, 'भारत के ७९वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले सभी तिब्बतियों की ओर से भारत सरकार और लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आज की दुनिया में, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र और अर्थव्यवस्था व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने वाला देश है। हम छह दशकों से भी अधिक समय से तिब्बती शरणार्थियों को भारत द्वारा दी गई सच्ची सहायता के लिए तहे दिल से आभारी हैं।'

तिब्बत के इतिहास पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, 'जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की, उसके ठीक बारह साल बाद चीनी आक्रमण के कारण तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, जिसके कारण हजारों तिब्बती निर्वासित हो गए। हमारे इतिहास के इस सबसे कठिन दौर में भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, जबकि देश अभी भी विकासशील है।'

उन्होंने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज जो कुछ भी हमारे पास है, वह भारत सरकार की कृपा से है। एक बार फिर मैं इस विशेष अवसर पर भारत के नेतृत्व और सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती हूं।'

◆ 3. डिप्टी स्पीकर डोलमा शेरिंग तेखांग ने फिल्म 'शोले' की ५०वीं वर्षगांठ पर गीत विमोचन समारोह में भाग लिया

१६ अगस्त, २०२५



धर्मशाला। डॉसिंग गॉड्स मोशन पिक्चर्स ने भारत के बॉलीवुड की विख्यात हिन्दी फिल्म 'शोले' रिलीज होने के ५० वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में १४ अगस्त २०२५ को एक गीत विमोचन का जश्न मनाया। इसके लिए धर्मशाला के गोल्ड सिनेमा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य भारत और तिब्बत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को उजागर करनेवाली सांस्कृतिक खूबियों को एकसाथ प्रदर्शित करना था।

तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान (टिपा) के प्रतिभाशाली कलाकारों के सहयोग से प्रदर्शित गए इस गीत विमोचन समारोह की कल्पना शोले की सिनेमाई विरासत और तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी।

लंदन से आए कलाकार रमन सिद्धार्थ ने वैश्विक स्तर पर तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना का मार्गदर्शन किया। रमन हिमाचल प्रदेश मूल के हैं और लंदन में उन्होंने अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ा है। अब वे अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं।

- तिब्बती संसदीय सचिवालय की रिपोर्ट

◆ 4. शिक्षा मंत्री थरलाम डोलमा चांगरा ने जर्मनी के 'इनिशिएटिव ओबरलैंड' के प्रतिनिधिमंडल के साथ संभूत मुख्यालय और पेटियन स्कूल का दौरा किया

२१ अगस्त, २०२५

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की शिक्षा मंत्री थरलाम डोलमा चांगरा ने आज २१ अगस्त की दोपहर को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संभूत तिब्बती स्कूल सोसाइटी (एसटीएसएस) के मुख्यालय और पेटियन स्कूल का दौरा किया। उनके साथ जर्मनी के 'इनिशिएटिव ओबरलैंड' के प्रतिनिधि भी थे, जिनका नेतृत्व उसकी अध्यक्ष मैडम एंजेलिका लेची रहीम कर रही थीं। उनके साथ उनके पति अलीबुल्ला अलेक्जेंडर रहीम, उनके बेटे स्टीफन अलेक्जेंडर रहीम और फील्ड डायरेक्टर वेन न्यिमा दोरजी भी थे।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत संभूत निदेशक शेरिंग धोंडुप ड्रोंगपा, उप निदेशक तेनजिन नागदोन, स्कूल के प्रधानाचार्य लेक्ष्य न्यिमा और परियोजना अधिकारी लोबसांग गोंपो ने किया।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत संभूत मीटिंग हॉल में दोपहर के भोजन के समय किया गया, जिसके बाद निदेशक कार्यालय में मुंडगोड स्थित दोगुलिंग तिब्बती बस्ती में चल रही परियोजना और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा हुई।

इससे पहले सुबह जर्मनी के इनिशिएटिव ओबरलैंड ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अंतर्गत गृह विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात की।

इस बैठक में सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती, मुंडगोड (दोगुलिंग) में चल रही परियोजना और भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल का गृह विभाग के कार्यकारी सचिव पाल्डेन धोंडुप, अतिरिक्त सचिव शेरिंग यूडन, दक्षिण अनुभाग प्रमुख और संबंधित कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

कल २० अगस्त को इनिशिएटिव ओबरलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मुंडगोड तिब्बती बस्ती की परियोजना और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें डीटीआर अस्पताल पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सचिव जम्पा फुंटसोक ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनके दीर्घकालिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।



शिक्षा विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से जर्मन प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। इस यात्रा ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और इनिशिएटिव ओबरलैंड जर्मनी जैसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच निरंतर सहयोग को लेकर ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से तिब्बती बस्तियों में शैक्षिक अवसरों को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को समर्थन देने में उनका सहयोग सराहनीय रहा है।

जर्मनी स्थित इनिशिएटिव ओबरलैंड संगठन की स्थापना १९९८ में मैडम एंजेलिका लेची रहीम की मां ने की थी और तब से इसे स्वयं मैडम एंजेलिका ने आगे बढ़ाया है।

अपनी स्थापना के बाद से संगठन ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के शिक्षा विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई परियोजनाओं के लिए योगदान किया है।

इसका मुख्य ध्यान मुंडगोड तिब्बती बस्ती पर है, जहां इसने शाक्य मठ, डीटीआर अस्पताल, वृद्धाश्रम और कई अन्य पहलों सहित विभिन्न संस्थानों को सहायता प्रदान की है।

◆ 5. प्रेस विज्ञप्ति: तिब्बती चुनाव आयोग ने २०२६ के आम चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया

१३ अगस्त, २०२५

प्रेस विज्ञप्ति

जैसे-जैसे २०२६ में सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया के बारे में काफी पूछताछ और सार्वजनिक चर्चा और अटकलें शुरू हो गई हैं। इसलिए, चुनाव आयोग इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर आम जनता को स्पष्टीकरण और जानकारी देना आवश्यक समझता है।

निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर के अनुच्छेद ९७(३)(५) और चुनाव नियमों और विनियमों के अनुच्छेद- २ के अनुसार, जिसमें यह प्रावधान है कि 'जब भी सिक्योंग और तिब्बती संसद के सदस्यों के चुनाव होने हैं, दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की आवश्यकता होगी। चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर उस दिन शुरू होती है, जिस दिन दोनों अतिरिक्त चुनाव आयुक्त पद की शपथ लेते हैं। उन दोनों का कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा से लेकर अंतिम चुनाव परिणामों की घोषणा तक होगा...' तदनुसार, चुनाव आयोग ने ०१ अक्टूबर २०२५ से दोनों अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने का अनुरोध किया है। दोनों अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों के पदभार ग्रहण करने के बाद चुनाव आयोग विस्तृत चुनावी प्रक्रिया और प्रारंभिक एवं अंतिम चुनावों की तिथियों की घोषणा करेगा। इसके बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों अतिरिक्त चुनाव आयुक्त ०१ अक्टूबर २०२५ से चुनाव नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तिब्बती प्रवासी समुदायों का आधिकारिक दौरा करेंगे।

इसलिए, हम तिब्बती जनता से सतर्क रहने और चुनाव के बारे में समाज में फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं से गुमराह न होने की पुरजोर अपील करते हैं।

१३ अगस्त २०२५

चुनाव आयोग

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन

◆ 6. लुधियाना के तिब्बती व्यापारी संघ ने परम पावन दलाई लामा के सम्मान में 'करुणा वर्ष' और भारत का ७९वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

१८ अगस्त, २०२५

लुधियाना (पंजाब)। भारत के ७९वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब के लुधियाना में तिब्बती व्यापारी संघ ने परम पावन १४वें दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'घोटन: करुणा वर्ष' के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम लुधियाना स्थित किंग पैलेस हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय और तिब्बती सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और परम पावन की गतिविधियों से संबंधित फोटो प्रदर्शनियां लगाई गईं।

तिब्बत होजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसी कपूर, दिल्ली जाफराबाद व्यापार संघ के अध्यक्ष अशरीफ, तिब्बती व्यापारी संघ की केंद्रीय समिति के पूर्व सदस्य और भारत भर के लगभग २३४ क्षेत्रों के व्यापारी संघों के प्रतिनिधि शामिल थे।

मुख्य कार्यक्रम से पहले दोपहर लगभग २ बजे सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा शेरिंग तेयखांग और न्यायिक आयुक्त दावा फुनकी और फगपा शेरिंग के साथ लुधियाना में तिब्बती व्यापारी संघ के नए कार्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।

मुख्य कार्यक्रम दोपहर ३ बजे तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद तिब्बती शहीदों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया।

इस कार्यक्रम में तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान (टीआईपीए) और निर्वासित समुदाय के विभिन्न गायकों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।



इस कार्यक्रम में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष डोल्मा शेरिंग तेयखांग, न्यायिक आयुक्त दावा फुनकी, न्यायिक आयुक्त फगपा शेरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर आचार्य येशी फुंटसोक, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य कर्मा गेलेक, वित्त विभाग के सचिव शेरिंग धोंडुप, दिल्ली के प्रतिनिधि जिग्मे जुंगने और तिब्बती कला प्रदर्शन संस्थान के निदेशक धोंडुप शेरिंग उपस्थित थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गोयल, भारत-तिब्बत संघ के सचिव सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल, भारत-तिब्बत संवाद मंच के सचिव कृष्ण भारद्वाज, भारत-तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, लाला तिब्बती होजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन सूद, भारत-

सम्मान स्वरूप, निर्वासित तिब्बती व्यापारी संघ ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों और व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों को औपचारिक खटक भेंट किए।

इस अवसर पर, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा इस वर्ष को 'करुणा वर्ष' घोषित करने का निर्णय तिब्बती समाज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण और पहलों को व्यापक रूप से प्रचारित करने का एक माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निर्वासित तिब्बती व्यापारी संघ की भी सराहना की, जिसने परम पावन के जन्मदिन और

भारत की स्वतंत्रता की ७९वीं वर्षगांठ- दोनों को सम्मानपूर्वक मनाया।

सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां भारत अपनी स्वतंत्रता के ७९वां वर्ष मना रहा है, वहीं तिब्बत ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के माल तीन वर्ष बाद ही अपनी स्वतंत्रता खो दी, जिसके परिणामस्वरूप तिब्बती लोग निर्वासित होकर शरणार्थी बन गए। उन्होंने दशकों से तिब्बती समुदाय को निरंतर और अटूट समर्थन देने के लिए भारत की केंद्र और राज्य सरकारों- दोनों के प्रति गहरा आभार प्रकट किया। इसके अलावा, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत (मेक इन इंडिया) की दिशा में प्रयास के महत्व पर जोर दिया और जहां भी संभव हो, आयात के स्थान पर स्वदेशी तकनीक और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा, उन्होंने परम पावन के जन्मदिन के सम्मान में इस वर्ष को 'करुणा वर्ष' के रूप में मनाने की बात कही और परम पावन के दर्शन को वैश्विक स्तर पर फैलाने के महत्व पर बल दिया। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने परम पावन की चार प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डाला।

अंत में, सिक्क्योंग ने तिब्बत और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और प्राकृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जिसमें उनके स्थायी धार्मिक संबंध भी शामिल हैं। उन्होंने तिब्बती समुदाय के छोटे व्यापारियों को भारतीय व्यापारिक नेताओं से मिले अपार समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिससे उनकी आजीविका में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि ये बहुमूल्य संबंध भविष्य में भी फलते-फूलते रहेंगे।

इसके बाद, निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोलमा शेरींग ने संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया गया कि तिब्बती समाज में परम पावन का जन्मदिन मनाना केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि तिब्बती पहचान को संरक्षित करने और परम पावन की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों का वर्णन किया, जब चीनी उत्पीड़न, अपनी मातृभूमि के खोने और कठोर शरणार्थी परिस्थितियों के बीच परम पावन १९५९ में एक शरणार्थी के रूप में पहली बार भारत आए थे। इन चुनौतियों के बावजूद, परम पावन के सच्चे नेतृत्व में भारत सरकार और जनता के सहयोग और समर्थन से धीरे-धीरे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, शैक्षिक बस्तियां और मठ स्थापित हुए। इन प्रयासों ने आज तक तिब्बती भाषा, संस्कृति और उसके नस्लीय पहचान को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। इस अवसर पर, उन्होंने भारत सरकार और जनता के निरंतर सहयोग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

उन्होंने दलाई लामा परंपरा की निरंतरता की पुष्टि करते हुए परम पावन की हालिया सार्वजनिक घोषणा पर भी प्रकाश डाला, जिसने न केवल तिब्बतियों और उनके अनुयायियों में, बल्कि पूरे विश्व में आशा का संचार किया है। यह देखते हुए कि इस वर्ष केंद्रीय तिब्बती प्रशासन परम पावन के जन्मदिन को 'करुणा वर्ष' के रूप में मना रहा है, उन्होंने सभी से परम पावन की करुणामयी गतिविधियों को विश्व स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के समापन पर, निर्वासित तिब्बती व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष

सोनम ढोंडन ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दिया और कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया।

◆ 7. . करुणा वर्ष में तिब्बती और कन्नड़ समुदाय द्वारा याद किए गए स्वर्गीय मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा

१३ अगस्त, २०२५

चिन्नदुर्ग। दक्षिण क्षेत्र के तिब्बती बस्तियों के मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय, मुंडगोड तिब्बती बस्ती कार्यालय, एसएसएस एम गुरु ट्रस्ट और कर्नाटक के तिब्बत समर्थक समूह ने संयुक्त रूप से १० अगस्त २०२५ को वर्ष भर चलने वाले 'करुणा वर्ष' समारोहों के तहत दक्षिण भारत के चिन्नदुर्ग में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एस. निजलिंगप्पा की करुणा को याद करने और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी।

दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री निजलिंगप्पा ने दक्षिण भारत में तिब्बतियों को उदारतापूर्वक व्यापक भूमि प्रदान की थी और परम पावन दलाई लामा ने अक्सर उनकी दयालुता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

उपस्थित मुख्य अतिथियों में परम पावन दलाई लामा ब्यूरो, दिल्ली के प्रतिनिधि जिग्मे जुंगनी और कर्नाटक सरकार के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इनमें वृहद एवं मध्यम उद्योग अवसंरचना विकास मंत्री माननीय श्री एम.बी. पाटिल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के मंत्री माननीय श्री के.एच. मुनियप्पा, योजना एवं सांख्यिकी मंत्री माननीय श्री डी. सुधाकर और श्रम मंत्री माननीय श्री संतोष लाड शामिल थे।

इनके साथ कार्यक्रम में सात स्वामीजी, राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी, भिक्षु और स्थानीय निवासी भी उपस्थित थे। इस तरह इस कार्यक्रम में लगभग ५०० लोगों ने भाग लिया।



कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तिब्बती प्रार्थनाओं से हुई, जिसके बाद मंत्रियों और विशिष्ट अतिथियों ने अपने भाषण दिए। अपने भाषणों में उन्होंने परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं और 'करुणा वर्ष' उत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा, सभा के समक्ष परम पावन दलाई लामा का एक संदेश कन्नड़ भाषा में पढ़कर सुनाया गया।

कार्यक्रम का समापन दक्षिण क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि और मुंडगोड टीएसओ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में निवास कर रहे सभी तिब्बतियों की ओर से भारत सरकार और दिवंगत मुख्यमंत्री के प्रति गहरा आभार और प्रशंसा व्यक्त की।

-टीएसओ, मुंडगोड की रिपोर्ट

◆ 8. कुल्लू-मनाली के तिब्बती समुदाय ने 'करुणा वर्ष' में पर्यावरण सफाई अभियान शुरू किया

१८ अगस्त, २०२५

कुल्लू-मनाली। 'करुणा वर्ष' और भारत के स्वतंत्रता दिवस की ७९वीं वर्षगांठ के अवसर पर कुल्लू-मनाली घोटन आयोजन समिति ने स्थानीय जिला सरकार के सहयोग से १५ अगस्त से पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यावरण सफाई अभियान का आयोजन किया इस अभियान में समुदाय के विभिन्न समूहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें कुल्लू और मनाली के निवासी, मनाली एसटीएस स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, धोबी पलराबलिंग तिब्बती बस्ती के सदस्य, भुंतर फुटसोक राऐनलिंग तिब्बती बस्ती के समुदाय के प्रतिनिधि, पतलीकुहल स्थित टीसीवी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और स्थानीय तिब्बती महिला संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। इस तरह कुल ७० से अधिक व्यक्तियों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से योगदान दिया।



कार्यक्रम का पहला दिन डुंगरी से शुरू होकर मनाली के रामबाग वन तक सफाई अभियान में बीता। कार्यक्रम के दौरान, कुल्लू-मनाली तिब्बती बस्ती अधिकारी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने इस वर्ष को करुणा वर्ष के रूप में मनाए जाने के महत्व पर बल दिया और समुदाय को व्यापक लाभ पहुंचाने वाली पहलों में शामिल होने की नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।

उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में मनाली नगर निगम की उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा और मनाली वन विभाग के रेंज अधिकारी टीटू शामिल थे। दोनों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

दूसरे दिन की गतिविधियां कुल्लू ढालपुर मैदान तक चलीं और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा शासित सड़कों और बाजार क्षेत्रों तक जारी रहीं। कुल्लू जिला सरकार के उपाध्यक्ष श्री चंदन प्रेमी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और एक औपचारिक भाषण दिया। उनके समर्थन के सम्मान में कुल्लू-मनाली टीएसओ ने उन्हें एक स्मारक घोटन स्मृति चिन्ह भेंट किया।

कार्यक्रम का समापन सकारात्मक रहा और सभी प्रतिभागियों को जलपान और स्नेक्स परोसे गए तथा पर्यावरण संरक्षण में उनके बहुमूल्य योगदान का जश मनाया गया।

-टीएसओ कुल्लू-मनाली की रिपोर्ट

◆ 9. चीन ने परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन समारोह के दौरान तिब्बतियों को सामूहिक हिरासत में लिया

१४ अगस्त, २०२५

धर्मशाला। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) सरकार ने परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन पर तिब्बतियों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रतिबंध लगा दिये। विश्वसनीय सूत्रों की रिपोर्ट है कि चीनी अधिकारियों ने करजे मठ में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कीं, जिससे भिक्षुओं और भिक्षुणियों को मठ परिसर के भीतर ही सीमित कर दिया गया है और उन्हें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या सामुदायिक अनुष्ठान में भाग लेने से रोक दिया गया। अधिकारियों ने घरों में किसी भी प्रकार का धुआं करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। यह संगसोल प्रार्थना अनुष्ठानों के दौरान जुनिपर की शाखाओं को जलाने की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथा है, जिसका उद्देश्य सौभाग्य लाना और दुर्भाग्य को दूर करना है। चीनी अधिकारियों ने इस प्रथा को दबाने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्रवाई की।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, परम पावन के ९०वें जन्मदिन के आसपास, चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है, जिसमें

उनके संवाद-संचार, विशेष रूप से निर्वासित लोगों के साथ और पूरे तिब्बत में उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उदाहरण के लिए, करजे के झाकगो काउंटी में, अधिकारियों ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर तिब्बती लोगों द्वारा की जानेवाली किसी भी सभा पर २३ जुलाई २०२५ तक रोक लगा दी है। कई तिब्बतियों को पारंपरिक अमदो प्रांत के बा जोंग और सिलिंग (चीनी: शिनिंग) में कैद कर लिया गया है या हिरासत में रखा गया है तो कुछ को काउंटी-स्तरीय सरकारी सुरक्षा कार्यालयों में रखा गया है। किसी भी स्थिति में कैद किए गए लोगों के रिश्तेदारों और परिवार और प्रियजनों को उनके ठिकाने और कुशल-क्षेम के बारे में कभी सूचित नहीं किया जा रहा है।



जुलाई में बीबीसी के पत्रकारों की एक टीम ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति के बारे में कई भिक्षुओं से बात करने के लिए न्गाबा स्थित कीर्ति मठ का दौरा किया। यात्रा के तुरंत बाद, चीनी अधिकारियों ने मठ पर कार्रवाई शुरू कर दी और कई भिक्षुओं से पूछताछ की।

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के प्रमुख कीर्ति मठों में धार्मिक स्वतंत्रता पर अपना शिकंजा कस दिया है और जुलाई २०२५ से आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी है। १३ जुलाई से सुरक्षा बलों ने न्गाबा काउंटी में न्गाबा कीर्ति मठ, जोगे काउंटी में तकसंग ल्हामो कीर्ति मठ और बरखम काउंटी में ग्यालरॉन्ग त्सोदुन कीर्ति मठ पर नए सिरे से व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अधिकारियों ने कथित तौर पर भिक्षुओं को कड़ी चेतावनी जारी की है और उन्हें निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता कीर्ति रिनपोछे से जुड़ी सभी तस्वीरों, लेखों और दस्तावेजों को नष्ट करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने धमकी दी है कि ऐसी सामग्री के साथ पकड़े गए किसी भी मठ पर 'राजनीतिक अपराध' का आरोप लगाया जाएगा। राजनीतिक अपराध चीन में एक गंभीर आरोप जिसका इस्तेमाल अक्सर लंबी जेल की सजा सहित कठोर सजा देने के लिए किया जाता है। कई महीने पहले, चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के चार प्रमुख कीर्ति मठों में से एक, गांसु प्रांत के सांगचू काउंटी स्थित, होर सांग कीर्ति मठ में कीर्ति रिनपोछे की तस्वीरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आदेश मठ के बाहर भी लागू है। भिक्षुओं के आवासों और यहां तक कि स्थानीय तिब्बती परिवारों को भी अपने पूजनीय आध्यात्मिक नेता की तस्वीरें रखने या प्रदर्शित करने की सख्त मनाही है।

चीनी अधिकारियों ने बौद्ध शैक्षिक प्रशासन समिति को बंद कर दिया है, जो अपने दार्शनिक अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध चार प्रमुख कीर्ति मठों का

प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख संस्था है। अधिकारियों ने समिति पर निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता कीर्ति रिनपोछे से संबंध रखने का आरोप लगाया था। एक व्यापक कार्रवाई में, सिचुआन प्रांत में न्गाबा स्वायत्त प्रिफेक्चर की सरकार ने काउंटी-स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कीर्ति रिनपोछे की तस्वीरों के प्रदर्शन पर संयुक्त रूप से प्रतिबंध लगा दिया।

परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन से पहले के महीनों में चीनी अधिकारियों ने चीन के किंगडै प्रांत में शामिल तिब्बती क्षेत्रों में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। विदेश से तिब्बत लौट रहे तिब्बतियों को मठों में प्रवेश करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोक दिया गया और इसके लिए कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। तिब्बत के अमदो क्षेत्र के सोशर प्रिफेक्चर के यादजी (चीनी: जुन्हुआ) में मठों को पांच से ज्यादा भिक्षुओं के एकत्र होने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लगभग २०० तिब्बतियों से परम पावन के जन्मदिन समारोह से कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की गई। इसके अलावा, कई प्रमुख तिब्बती मठों में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बड़ी प्रार्थनाएं और सभाएं आयोजित करने से रोक दिया गया।

अमदो प्रांत के सोजांग (चीनी: हैबेई) प्रिफेक्चर के कांगत्सा (चीनी: गंगचा) काउंटी में चीनी अधिकारियों ने दलाई लामा के ९०वें जन्म दिवस वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जन्मदिन मनाने के आशंकित तिब्बतियों पर निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा अधिकारियों ने पहचान पत्र की जांच की है और निवासियों को अपने निजी जन्मदिन समारोहों की तस्वीरें स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा कार्यालयों में जमा करने का आदेश दिया है।

चीनी अधिकारियों ने २५ जुलाई २०२५ को अमदो के माल्हो प्रिफेक्चर के चेन्त्सा (चीनी: जियांजा) काउंटी में दो तिब्बतियों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया और दोनों के ठिकाने और कुशल-क्षेम नहीं बताने के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

तिब्बती राजधानी ल्हासा और माल्द्रोंगंगकर सहित तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि ल्हासा शहर में बड़ी संख्या में सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। माल्द्रोंगंगकर में चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर तिब्बतियों को सांगसोल करने से रोकने के आदेश जारी किए हैं, जहां तिब्बती अक्सर पहाड़ियों या छतों पर धूप और जुनिपर की शाखाएं जलाते हैं।

इस वर्ष के कड़े कदम तिब्बत में धार्मिक जीवन, खासकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण तिथियों के दौरान चीनी नियंत्रण के व्यापक चलन का हिस्सा हैं। यह धमकियों और दंडों का उपयोग करके परम पावन दलाई लामा के साथ तिब्बतियों के संबंधों को तोड़ने की एक सोची-समझी चाल भी है। जारी प्रतिबंध पीआरसी द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा के साथ-साथ उसके अपने संविधान सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के व्यवस्थित उल्लंघन का प्रतीक हैं, जो कम से कम कागजों पर, सरकार के हस्तक्षेप के बिना किसी के धर्म का स्वतंत्र

रूप से पालन करने के अधिकार की रक्षा करते हैं।

– केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डीआईआईआर में तिब्बत एडवोकेसी अनुभाग के तहत संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क की रिपोर्ट

◆ 10. तिब्बत की नदी पर जल-युद्ध तेज करने की चीनी रणनीति

०४ अगस्त, २०२५

अरुणाचल प्रदेश के पास यारलुंग सांगपो पर चीन के विशाल बांध के कारण बदले हुए जल प्रवाह से भारत, भूटान और बांग्लादेश को भू-राजनीतिक जोखिमों का खतरा है। इस तरह पानी रणनीतिक हथियार बन सकता है।

- बॉर्डरलैंस में सावांग दोरजी जेशोंग और कलसांग डोलमा

०२ अगस्त २०२५

यारलुंग सांगपो के निचले क्षेत्र में चीन द्वारा बनाया जा रहा विशाल बांध हिमालय के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल रहा है, जिससे तिब्बत से निकलनेवाले इस नद को लेकर दक्षिण एशिया के विरुद्ध चीन का जल-युद्ध और तेज हो रहा है। अगर हिमालय को लेकर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है, तो पूर्वी हिमालय अगला युद्धक्षेत्र होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि चीनी अधिकारी तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर जलविद्युत बांधों के रूप में एक जल-बम बना रहे हैं। इसके भारत, भूटान और बांग्लादेश पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।

सीमा पार जल संसाधनों पर नियंत्रण की चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को उजागर करने वाले एक कदम में, बीजिंग ने पिछले साल दिसंबर में घोषित अपनी १४वीं पंचवर्षीय योजना में यारलुंग सांगपो पर एक विशाल जलविद्युत बांध के निर्माण को औपचारिक रूप से शामिल किया है। १९ जुलाई को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने तिब्बत के न्यिंगची शहर में नदी के निचले इलाकों में बांध के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बगल में स्थित है।

इस परियोजना के दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत केंद्र बनने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन ३०० अरब किलोवाट-प्रतिघंटे बिजली है, जो श्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना बड़ा है। यह बांध यारलुंग सांगपो के दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश से ठीक पहले नद के निचले हिस्से में बनाया जा रहा है, जहां यह ग्रेट बेंड पर यू-टर्न लेता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। यही पर यह ब्रह्मपुत्र नद बन जाता है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ली ने चाइना याजियांग ग्रुप का भी परिचय कराया, जो एक नव स्थापित सरकारी उद्यम है। इसे ही बांध के विकास की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस परियोजना की

अनुमानित लागत कम से कम १७० अरब डॉलर है और इसमें न्यिंगची के चारों ओर पांच जलप्रपात बांधों का निर्माण शामिल होगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि इंजीनियर नद के कुछ मोड़ों को सीधा करने और प्रवाह एवं बिजली उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए सुरंगों के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने की योजना बना रहे हैं।

इस वर्ष की शुरुआत में चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग ने भी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को सौंपी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बांध और हांगकांग क्षेत्र से जुड़ी एक संबंधित बिजली परीक्षण लाइन को शामिल किया था, जिसमें परियोजना के राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया था।

परियोजना के स्थान ने भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी बड़े भूकंप से अगर बांध के ढांचे को नुकसान होता है, तो यह निचले तटवर्ती क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनेगा। पर्यावरणविदों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों ने भी पारिस्थितिकीय प्रभाव और प्रभावित होनेवाले निचले क्षेत्र देशों के साथ परामर्श न किये जाने पर चिंता जताई है।

चीन का दावा है कि यारलुंग सांगपो जलविद्युत परियोजना उसकी 'पश्चिम से पूर्व विद्युत हस्तांतरण परियोजना (西电东送, जिडियन डोंगसोंग)' का हिस्सा है, जो संसाधन संपन्न पश्चिमी क्षेत्रों में उत्पादित बिजली को औद्योगिक और घनी आबादी वाले पूर्वी प्रांतों में भेजने की दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति है। लेकिन उस हरित, तकनीकी भाषा के पीछे जल नियंत्रण, क्षेत्रीय प्रभाव और सीमा पर दावे से जुड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं।

यह परियोजना चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के अनुरूप है और यह क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में बीजिंग की बढ़ती दृढ़ता को दर्शाती है। भारतीय सीमा से केवल ३० किमी दूर तिब्बत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील मेडोग क्षेत्र में स्थित यह परियोजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि समकालीन भू-राजनीति में बुनियादी ढांचे का उपयोग शासन कला के एक साधन के रूप में कैसे तेजी से किया जा रहा है।

यारलुंग सांगपो नद तिब्बत से निकलता है और भारत से होते हुए बांग्लादेश में समुद्र में मिल जाता है। इसे भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सीमा पार के किसी भी ऊपरी इलाके के देश द्वारा किया गया एकतरफा हस्तक्षेप, जैसे कि बांध निर्माण, जल प्रवाह में बदलाव, कृषि को खतरे में डालकर और पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़कर, निचले इलाके के देशों को सीधे प्रभावित करता है। पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, ऐसा नियंत्रण चीन को भारत और बांग्लादेश पर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक लाभ भी देता है, जिससे जल क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा में रणनीतिक प्रभाव का एक संभावित साधन बन जाता है।

जब बीजिंग ने पिछले दिसंबर में बांध परियोजना की औपचारिक घोषणा की, तो भारत और बांग्लादेश दोनों ने इसके संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जनवरी तक, भारत के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग के साथ आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया था। 'चीनी पक्ष

से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में गतिविधियों से डाउनस्ट्रीम राज्यों के हितों को नुकसान न पहुंचे।'

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने हाल ही में इस परियोजना को एक 'वॉटर बम' बताया था, और स्थानीय जनजातियों और आजीविका के लिए संभावित खतरे की चेतावनी दी थी। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा था, 'मुद्दा यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता... यह काफी गंभीर है, क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के 'वॉटर बम' के रूप में भी कर सकता है।'

ये चिंताएं नई नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक- लोवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि तिब्बती पठार से निकलने वाली नदियों पर नियंत्रण, चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभावी रूप से 'दबाव' डालने का मौका देता है, जिससे पानी के रणनीतिक हथियार बनने की आशंकाएं और प्रबल हो जाती हैं।

चीन द्वारा यारलुंग सांगपो बांध का शिलान्यास करने के ठीक एक दिन बाद अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने कहा, 'चीन ने पहले ही अपना बांध निर्माण शुरू कर दिया है और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कार्रवाई करनी होगी और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह भारत की भविष्य की जल सुरक्षा के बारे में है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है।'

यारलुंग सांगपो बांध परियोजना, तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के पीछे की गहरी राजनीतिक चाल को उजागर करती है। यह परियोजना विशुद्ध रूप से विकासात्मक या पर्यावरणीय पहल होने से कहीं अधिक क्षेत्र में अपने अधिकार और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की बीजिंग की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि कितने लोग विस्थापित हो सकते हैं, फिर भी स्पष्ट है कि तिब्बती समुदायों को स्थायी रूप से पुनर्वास का सामना करना पड़ रहा है, जो 'आधुनिकीकरण' की आड़ में जबरन पुनर्वास के पुराने तरीकों की याद दिलाता है। इन जबरन विस्थापनों के परिणामस्वरूप अक्सर पैतृक भूमि, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक आजीविका का नुकसान होता है। इससे चीनी शासन के तहत तिब्बतियों द्वारा अनुभव किए गए ऐतिहासिक हाशिए पर रहने की विभीषिका और भी भीषण हो जाती है।

बीजिंग अपने क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के अपने संप्रभु अधिकार का दावा करता है और इस परियोजना को एक हरित ऊर्जा पहल के रूप में प्रस्तुत करता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, प्रदूषण में कमी लाएगी और ग्रामीण तिब्बतियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी। चीनी सरकारी मीडिया अक्सर इन विशाल बांधों को विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए 'दोनों पक्षों की जीत' वाला बताता है। हालांकि, चीन के इस कथन को तिब्बती विद्वान और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक गलत बताते हैं। वे इस परियोजना को एक अत्यंत संवेदनशील सीमांत क्षेत्र में संसाधन दोहन और राजनीतिक दमन के अकाट्य हथियार के रूप में देखते हैं।

राजनीतिक रूप से चीन यारलुंग सांगपो परियोजना को लेकर इस क्षेत्र

और उसके बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक योजना बना रहा है।

नद पर नियंत्रण करके चीन तिब्बत के पानी का उपयोग भारत के खिलाफ जल युद्ध के लिए कर रहा है। इस मामले में यह बांध न केवल एक ऊर्जा अवसंरचना बन जाता है, बल्कि दक्षिण एशिया में चीन की भू-राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक हथियार भी बन जाता है।

11. चीन कॉलेज प्रवेश परीक्षा में तिब्बती भाषा को प्रतिबंधित करेगा

०७ अगस्त, २०२५

-फाइनेंशियल टाइम्स

चीन तिब्बत क्षेत्र में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में तिब्बती भाषा को प्रतिबंधित करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चीन स्वायत्त क्षेत्र के अधिकांश छात्रों के लिए राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा से तिब्बती भाषा को मुख्य विषय के रूप में हटाने की योजना बना रहा है, जिससे इस भाषा के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।



तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष गामा सेडेन ने इस सप्ताह एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह बदलाव राष्ट्रीय परीक्षा में सुधारों का हिस्सा है और इससे तिब्बतियों के करियर की संभावनाओं में सुधार होगा।

उन्होंने कहा, 'अन्य प्रांतों और क्षेत्रों की तरह तिब्बत में भी चीनी भाषा और गणित जैसे 'एकीकृत परीक्षा विषय' होंगे। अंग्रेजी, रूसी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं तो होंगी। लेकिन, तिब्बती भाषा परीक्षा में मुख्य विषय नहीं होगी।

उन्होंने इन बदलावों के बारे में कहा, 'इससे सभी नस्लीय समूहों के छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, अल्पसंख्यक छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उनकी समग्र वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साक्षरता में सुधार होगा।' इस बहिष्कार से अमेरिका और विदेशों में रहने वाले तिब्बतियों के उन आरोपों को बल

मिलेगा कि चीन इस क्षेत्र के धार्मिक अधिकारियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में लाने और उनकी संस्कृति के पहलुओं को दबाने के लिए 'चीनीकरण' अभियान का विस्तार कर रहा है। हालांकि, बीजिंग ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया है।

गामा सेडेन ने इस बदलाव के कार्यान्वयन की कोई समय-सीमा नहीं बताई, केवल इतना कहा कि तिब्बत में शिक्षा सुधार २०२४ से ही शुरू हो चुके हैं। लेकिन छह तिब्बती प्रिफेक्चर के अधिकारियों ने कहा कि यह अगले साल लागू होगा।

भारत के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार से जुड़े अधिकारी, जो इन बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, ने चीन पर इस क्षेत्र में तिब्बती भाषा के इस्तेमाल को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

निर्वासित तिब्बती सरकार से संबद्ध धर्मशाला स्थित तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक दावा शेरींग ने कहा, 'एक बार जब आपकी प्रवेश परीक्षा में तिब्बती भाषा नहीं होती, तो यह संचार का कोई कानूनी साधन नहीं रह जाती या किसी पेशे की तलाश या नौकरी पाने के लिए उपयोगी नहीं रह जाती।'।

हर साल पूरे चीन में हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र कठिन, बहु-दिवसीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा देते हैं, जिसे गाओकाओ के नाम से जाना जाता है। चीनी, गणित और विदेशी भाषाओं के अलावा, छात्र राजनीति, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सहित कई विषयों में से चुनते हैं, जो सभी मंदारिन में पढ़ाए जाते हैं।

कुछ क्षेत्रों में, नस्लीय अल्पसंख्यक छात्रों को अपनी मूल भाषा में एक विषय की परीक्षा देने की अनुमति है।

लेकिन स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, २०२६ से केवल तिब्बती साहित्य जैसे विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों के लिए आवेदन करने वाले तिब्बती छात्र ही तिब्बती भाषा विषय की परीक्षा दे पाएंगे, जिसमें तिब्बती छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है।

गामा सेडेन ने ब्रीफिंग में बताया, 'सामान्य विश्वविद्यालयों में तिब्बती भाषा शिक्षण कार्यक्रमों में तिब्बती भाषा और साहित्य तथा तिब्बती चिकित्सा एवं औषध विज्ञान के लिए अपेक्षाकृत सीमित नामांकन कोटा, आगे की शिक्षा के लिए संकीर्ण रास्ते, विषय विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण सीमाएं और संकीर्ण रोजगार बाजार जैसी समस्याएं हैं।'।

उन्होंने कहा कि तिब्बती भाषा इस क्षेत्र के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों और तिब्बती आबादी वाले अन्य क्षेत्रों में एक मुख्य विषय बनी रहेगी।

तिब्बत नीति संस्थान के शेरींग ने सरकार पर 'शिक्षा, व्यवसाय, यात्रा और कार्यालय के काम' के लिए तिब्बती भाषा के उपयोग को 'पूरी तरह से समाप्त' करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

चीन के शिक्षा मंत्रालय और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार प्रतिक्रिया के तिब्बत देश

लिए किए गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

चीनी नेता शी जिनपिंग ने हाल के वर्षों में देश के नस्लीय अल्पसंख्यकों को हान-प्रधान समाज में विलय करने का दबाव बढ़ा दिया है।

इस पर प्रतिक्रिया का अनुरोध करने पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'चीनी सरकार तिब्बत की उत्कृष्ट पारंपरिक संस्कृति की रक्षा और विकास तथा तिब्बती सांस्कृतिक उपक्रमों की समृद्धि को बढ़ावा देने को बहुत महत्व देती है, और सभी नस्लीय समूहों के रीति-रिवाजों और आदतों का पूरा सम्मान करती है।'।

भीतरी मंगोलिया में सरकार ने मंगोलियन भाषा में कक्षा को कम कर दिया है, जिसके कारण २०२० में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

सुदूर पश्चिमी झिंझियांग में अधिकारियों ने उग्यूरों की धार्मिक रीति-रिवाजों, शिक्षा और संस्कृति पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उग्यूर एक मुस्लिम, तुर्क भाषा बोलने वाला समुदाय है जिन्हें सामूहिक हिरासत के बाद निगरानी के तहत रखा जाता है और उन्हें यात्रा से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तिब्बत की परीक्षा में बदलावों के बारे में हाल के महीनों में शिक्षकों और छात्रों को मौखिक रूप से सूचित किया गया था।

◆ 12. अमेरिकी विदेश विभाग ने तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति को गंभीर बताया

१९ अगस्त, २०२५

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा २०२४ की मानवाधिकार गतिविधियों पर पेश की गई रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश की गई है। इसमें जबरन गायब किए जाने, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और विदेशों में तिब्बतियों के अंतरराष्ट्रीय दमन सहित व्यापक उल्लंघनों का हवाला दिया गया है। १३ अगस्त २०२५ को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में समग्र स्थिति में 'कोई महत्वपूर्ण बदलाव' नहीं आया है। विश्वसनीय रिपोर्टों में यातना, अपमानजनक व्यवहार, सेंसरशिप और अभिव्यक्ति, धर्म और सभा की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंधों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की सरकार ने दुर्व्यवहारों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन रिपोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, विशेष रूप से तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की अभिव्यक्ति पर, कड़े नियंत्रणों पर प्रकाश डालती है। जिन तिब्बतियों ने सरकार की

नस्ली एकीकरण नीतियों की आलोचना की और खासकर परम पावन दलाई लामा, पंचेन लामा और तिब्बती भाषा शिक्षा के संबंध में चीनी नीति का विरोध किया, उन्हें उत्पीड़न, निगरानी और हिरासत का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक २६ वर्षीय तिब्बती भिक्षु, जिसका नाम सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा गया है, को बिना वारंट के हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर वीचैट पर काउंटी कानून की आलोचना में एक टिप्पणी पोस्ट की थी। इसके बाद उसके मठ में लगभग १०० भिक्षुओं के लिए १० दिनों का राजनीतिक 'पुनर्शिक्षा अभियान' चलाया गया था।

चीनी अधिकारियों ने विदेशी और घरेलू मीडिया की पहुंच पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। पत्रकारों को विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जो शायद ही कभी दिए जाते हैं। और जिन्हें अंदर जाने दिया जाता भी है, तो उन्हें निगरानी में रखा जाता है और कई तरह की चेतावनियां दी जाती हैं। तिब्बती लेखकों और ब्लॉगर्स के काम को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, तो उन पर गिरफ्तारी, उनकी जाँच जाने या सरकारी सेवाओं से वंचित होने का खतरा हमेशा रहता है।

तिब्बती कार्यकर्ताओं और धार्मिक अनुयायियों पर निशाना पर्यावरण कार्यकर्ता सोगोन शेरिंग को एक चीनी निर्माण कंपनी पर अवैध खनन गतिविधियों का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने के बाद आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। रिपोर्ट में भिक्षु लोसेल की हिरासत में हुई मौत का भी जिक्र है, जहां उन्हें कथित तौर पर अमानवीय यातनाएं दी गईं और चिकित्सा सेवा से वंचित रखा गया। चीनी अधिकारियों ने परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें रखने पर प्रतिबंध और कड़ा कर दिया और ऑनलाइन धार्मिक अभिव्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें प्रार्थना सभाएं और धार्मिक समारोह आयोजित करना भी शामिल है। यात्रियों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। उनसे धार्मिक हस्तियों की तस्वीरें ले जाने या उनके बारे में संदेश भेजने के लिए पूछताछ की जाती है।

सेंसरशिप और सूचना नियंत्रण रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी अधिकारी तिब्बत में तिब्बतियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक प्रतिबंध लगाते रहे हैं। वे मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पाठ्य-सामग्री के साथ-साथ ऐतिहासिक या राजनीतिक रूप से संवेदनशील शैक्षणिक पुस्तकों के प्रकाशन को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है।'

जुलाई में रेडियो फ्री एशिया ने निगरानी बढ़ा दिए जाने की सूचना देते हुए बताया कि अधिकारियों ने परम पावन दलाई लामा की तस्वीरों की जांच के लिए ल्हासा और शिगात्से के बीच यात्रियों को रोका और उनके जन्मदिन पर तिब्बत के बाहर के लोगों के साथ संचार पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'टीएआर' इंटरनेट और सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी, जबकि अधिकारियों ने तिब्बती क्षेत्रों में आरएफए तिब्बती और मंदारिन भाषा की सेवाओं के साथ-साथ नॉर्वे स्थित एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन- वॉयस ऑफ तिब्बत- की सेवाओं को भी बाधित कर दिया।

इसके अलावा, २०२३ में चीनी अधिकारियों ने एक नियम लागू करके तिब्बती धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। इससे भिक्षुओं और लेखकों को धार्मिक सामग्री ऑनलाइन साझा करने पर प्रतिबंध लग गया है। साथ ही बिना लाइसेंस वाली ऑनलाइन धार्मिक गतिविधियों और प्रसारणों पर भी रोक लगा दी गई है। मठवासी वेशभूषा में तिब्बतियों को भी चौकियों, हवाई अड्डों और अन्य याता केंद्रों पर कड़ी पुलिस जांच का सामना करना पड़ रहा है।

जबरन लापता, अपहरण और मनमाना हिरासत रिपोर्ट में चीन द्वारा तिब्बतियों को जबरन गायब कर दिए जाने और उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के निरंतर प्रयोग का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये कार्रवाइयां मानवाधिकार के बुनियादी संरक्षणों का उल्लंघन है। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने पिछले चार वर्षों में जबरन गायब होने के ६३ मामलों की सूचना दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि प्रतिशोध के डर से कम रिपोर्टिंग की आशंका है। वास्तविक संख्या संभवतः अधिक हो सकती है। एक उल्लेखनीय मामला तिब्बत के अमदो प्रांत के कीर्ति मठ के एक भिक्षु पेमा का था, जिन्हें अप्रैल २०२४ में परम पावन दलाई लामा के चिल के साथ एकल विरोध प्रदर्शन करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने न तो उनकी हिरासत की पुष्टि की और न ही उनके ठिकाने का खुलासा किया। सितंबर २०२४ में, कीर्ति मठ के दो भिक्षुओं सहित चार तिब्बतियों को बिना किसी सूचना के हिरासत में लिया गया और उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। चीन १९९५ में अपहरण के बाद से ३० वर्षों तक ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा के बारे में सही जानकारी छिपाता रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशेषज्ञों ने भी २०१३ और २०१८ के बीच गिरफ्तार किए गए नौ तिब्बती पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर चिंता व्यक्त की, जिनमें ए-न्या सेंगद्रा और दोरजी डाकटल शामिल हैं। इनके द्वारा उन पर चले मुकदमों, सजा या कानूनी और चिकित्सा सहायता तक पहुंच में पारदर्शिता की कमी पाई गई।

तिब्बतियों पर अत्याचार और अमानवीय व्यवहार चीनी अधिकारी तिब्बती कैदियों और कैदियों को यातना देते हैं, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और जबरन श्रम कराते हैं। हालांकि, कानून में इस तरह की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रिपोर्टों में लंबे समय तक एकांतवास, भोजन, नींद और धूप से वंचित रखने और जबरन पुनर्शिक्षा जैसे मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारों पर प्रकाश डाला गया है। नवंबर में तिब्बत टाइम्स ने बताया कि सेरा थेक्चेन लिंग मठ के एक भिक्षु लोसेल की जेल में बुरी तरह पिटाई किए जाने और चिकित्सा देखभाल से वंचित रखने के कारण मृत्यु हो गई। रिहा किए गए अन्य कैदियों ने कठोर हिरासत स्थितियों के कारण स्थायी विकलांगता और स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालिक क्षति का वर्णन किया है। इस मुकदमों के आरोपी बड़ी संख्या में निर्दोष पाए गए, लेकिन गैरकानूनी हत्याओं या पिछले दुर्व्यवहारों के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमन रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने विदेशों में रहने वाले तिब्बतियों, जिनमें भारत और नेपाल में लगभग

१,५०,००० तिब्बती शामिल हैं, को निशाना बनाकर व्यापक अंतरराष्ट्रीय दमन शुरू किया है। रिपोर्ट में तिब्बती प्रवासियों के खिलाफ उत्पीड़न, निगरानी और जबरदस्ती करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तिब्बती संस्थानों पर साइबर हमले, चीनी वाणिज्य दूतावासों में पारिवारिक जानकारी का जबरन खुलासा और विदेशों में सक्रियता को दबाने के लिए तिब्बत में रिश्तेदारों को धमकाना शामिल है। टीसीएचआरडी ने २०२२ के मध्य और २०२३ के अंत के बीच इन युक्तियों में वृद्धि दर्ज की है, जिसमें पारिवारिक संबंधों को तोड़ने, प्रवासी नेटवर्क में घुसपैठ करने और गलत सूचना फैलाने के प्रयास शामिल हैं। अधिकारियों ने पासपोर्ट में देरी या इनकार करके, वैध पासपोर्ट जब्त करके और विदेश में यात्रियों द्वारा चीनी नीति के खिलाफ बोलने पर तिब्बत में उनके परिवारों को धमकी देकर तिब्बतियों के आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जबरन श्रम और आर्थिक शोषण रिपोर्ट में चीन के श्रम कार्यक्रमों पर भी चिंता जताई गई है, जो गरीबी उन्मूलन की आड़ में ग्रामीण तिब्बतियों को कार्य योजनाओं में स्थानांतरित करते हैं। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन द्वारा जुलाई में किए गए एक अध्ययन में खनन क्षेत्र में जबरन श्रम के जोखिमों का हवाला दिया गया है, जो व्यापक अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को प्रतिध्वनित करता है।

निष्कर्ष तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति हर साल बिगड़ती जा रही है, जहां धर्म, संस्कृति और भाषा के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करने के कारण अन्यायपूर्ण ढंग से गिरफ्तार और जेल में बंद तिब्बतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और यहां तक कि चीन के अपने संविधान के तहत भी इन स्वतंत्रताओं के लिए गारंटी दी गई है, फिर भी तिब्बती पहचान को दबाने और आत्मसात करने के व्यापक अभियान के तहत इन्हें व्यवस्थित रूप से नकारा जा रहा है। नई नीतियां और निर्देश लागू किए गए हैं, जो तिब्बती पहचान की अभिव्यक्ति को प्रभावी रूप से आपराधिक बनाते हैं और तिब्बतियों को उसके लिए दंडित करने का कानूनी मौका देते हैं।

२०२४ की रिपोर्ट में न्यायेतर हत्याओं का दस्तावेजीकरण किया गया है और व्यापक आरोप मुक्ति और जवाबदेही की कमी के बने रहने पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति कठोर रूप से दमनकारी बनी हुई है और इसमें सार्थक प्रगति के बहुत कम संकेत हैं।

◆ 13. चीनी दुर्व्यवहार के बाद होटल से कूदने वाली कैदी तिब्बती उद्यमी की बहन गंभीर

२१ अगस्त, २०२५

धर्मशाला। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी पुलिस द्वारा बार-बार किए गए हमले और दुर्व्यवहार के कारण जेल में बंद तिब्बती उद्यमी और राजनीतिक कैदी दोरजी ताशी की बहन गोनपो क्यी कथित तौर पर एक होटल की दूसरी मंजिल से कूद गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है।

विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, गोनपो क्यी अपने भाई दोरजी ताशी और उनके वकील से मिलने के अपने कानूनी अधिकारों की अपील करने के लिए १८ अगस्त २०२५ को ल्हासा गई थीं। हालांकि, उनकी शांतिपूर्ण अपीलों का चीनी पुलिस ने गैरकानूनी माना और उन पर हिंसक हमला किया। कथित तौर पर सादे कपड़ों में चीनी पुलिस ने गोनपो क्यी को सड़कों पर घसीटा, उनकी पिटाई की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

चीनी पुलिस ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें जबरन याक होटल में बंद कर दिया। जब उन्होंने होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उनके साथ फिर से दुर्व्यवहार किया। उन्हें वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर पटक दिया। उनके होटल छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी और सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए होटल के अंदर और बाहर तैनात हो गए।

चीनी पुलिस ने २० अगस्त की सुबह उन्हें फिर से घेर लिया, कथित तौर पर उनकी पिटाई की और उनकी आजादी पर और भी पाबंदियां लगा दीं। हताशा और गुस्से में, गोनपो क्यी ने कथित तौर पर इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसे स्रोतों के अनुसार दुर्व्यवहार के बीच एक हताशा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। उनकी कमर और अंगों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। चीनी पुलिस ने घटना के बाद गोनपो क्यी को समय पर अस्पताल और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

जिस होटल में उन्हें १८ से २० अगस्त के बीच जबरन रखा गया था, वहां से रिकॉर्ड किए गए पांच वीडियो में गोनपो क्यी चीनी अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के खुलेआम उल्लंघन की निंदा करती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, 'मैं अपने भाई से मिलने आई थी, जो चीनी कानून के तहत मेरा कानूनी अधिकार है। इसके बजाय, उन्होंने मुझे एक कैदी की तरह बंद कर दिया है, मुझे पतल देने या अपने भाई और उसके वकील से मिलने का मौका नहीं दिया। मेरे पैर और कमर दोनों में गंभीर चोटें आई हैं। यह निर्विवाद है कि दोरजी को गलत तरीके से कैद किया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उन्हें काली टोपी पहनाकर अपराधी बनाया गया हो।'

एक क्लिप में, एक महिला ने उनसे विरोध किया और उनसे रिकॉर्डिंग बंद

करने को कहा। गोनपो क्यी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि हालांकि वह उस समय तस्वीरें नहीं ले रही थीं, लेकिन अगर वह चाहें तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। ये गवाहियां चीन द्वारा व्यवस्थित दमन और तिब्बतियों के बुनियादी अधिकारों के निर्मम हनन को उजागर करती हैं, भले ही इन अधिकारों को उसके अपने कानूनों में ही गारंटी दी गई हो।

न्याय के लिए लंबी लड़ाई दोरजी ताशी कभी एक सफल तिब्बती व्यवसायी थे। उन्हें २००८ में तिब्बत में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में महीनों तक यातनाएं दी गईं। २०१० में ल्हासा इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई में उन्हें ऋण धोखाधड़ी के मनगढ़ंत आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि मामला वास्तव में राजनीति से प्रेरित था। उनके भाई, दोरजी सेतेन को भी उसी समय छह साल की जेल की सजा सुनाई गई और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

सजा के बाद से दोरजी ताशी के परिवार ने कई बार और कई तरीकों से मामले की कानूनी समीक्षा की मांग की है। २०२० में, चीनी अदालत ने उनके मामले पर पुनर्विचार के लिए उनके वकील और रिश्तेदारों द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। २०२३ और २०२४ के बीच गोनपो क्यी ने अपने पति चोएक्योंग और भाई दोरजी सेतेन के साथ ल्हासा में सरकारी कार्यालयों और अदालतों के बाहर सात से ज्यादा शांतिपूर्ण भूख-हड़तालें और प्रार्थना प्रदर्शन किए। उनकी कार्रवाइयों के जवाब में चीनी अधिकारियों ने उन्हें बार-बार हिरासत में लिया और उनके साथ हिंसा की।

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब तथाकथित 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' गैरकानूनी चीनी शासन के तहत अपनी स्थापना की ६०वीं वर्षगांठ मना रहा है और अधिकारी पूरे ल्हासा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। इस बीच, दोरजी ताशी के भाई दोरजी सेतेन को कथित तौर पर ल्हासा से जबरन दक्षिणी तिब्बत स्थानांतरित कर दिया गया है और उनके लौटने पर रोक लगा दी गई है। वर्षों के शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद, अधिकारी परिवार को कानूनी प्रतिनिधित्व और मुलाकात के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

दोरजी ताशी को राजनीति से प्रेरित आरोपों में कैद करना चीन की असुरक्षा और प्रमुख तिब्बतियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को उजागर करता है। ताशी को चीनी दमन के खिलाफ तिब्बत के समर्थन में बोलने के लिए निशाना बनाया गया और कड़ी सजा दी गई। ये कार्रवाइयां चीनी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विपरीत हैं। चीन को ऐसी कार्रवाइयों को समाप्त करना चाहिए और तिब्बती लोगों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा किया है।

- सीटीए के डीआईआईआर में तिब्बत एडवोकेसी अनुभाग में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क द्वारा तैयार रिपोर्ट

◆ 14. तिब्बत के भिक्षु शेरसांग ग्यात्सो ने चीनी दमन के विरोध में सांग मठ में आत्महत्या की

२५ अगस्त, २०२५



धर्मशाला। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में मठों पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। सांग मठ (तिब्बती: གཤང་དགོན་པ།) से १८ वर्ष से कम आयु के सभी भिक्षुओं को निष्कासित कर दिया गया है और भिक्षुओं पर कड़े नियंत्रण और भारी दबाव डाले जा रहे हैं। विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, इन सख्त उपायों के विरोध में वरिष्ठ भिक्षु शेरसांग ग्यात्सो ने मठ में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

१८ अगस्त को, तिब्बत के पारंपरिक प्रांत अमदो के बा काउंटी में सांग मठ की प्रशासनिक समिति के प्रमुख तिब्बती भिक्षु शेरसांग ग्यात्सो ने मठ की दुकान की ऊपरी मंजिल पर आत्महत्या कर ली। उनकी आयु ५२ वर्ष थी। उनकी मृत्यु चीनी सरकार द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में हुई है, जिससे भिक्षुओं, विशेषकर नेतृत्वकारी पदों पर आसीन भिक्षुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मठ और आसपास के तिब्बती समुदाय अभी भी सख्त सरकारी नियंत्रण में हैं, जिससे घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और फोटो साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन के आसपास के दिनों में चीनी अधिकारियों ने सांग मठ में गहन जांच-पड़ताल की, जहां पुलिस ने भिक्षुओं के आवासों की कमरे-दर-कमरे तलाशी ली। अधिकारियों ने कथित तौर पर कुछ भिक्षुओं के पास मिली परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें जब्त कर लीं। तलाशी के बाद मठ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और भिक्षुओं की आवाजाही पर भारी प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकारियों ने १८ वर्ष से कम आयु के सभी भिक्षुओं को मठ से निष्कासित भी कर दिया।

अधिकारियों ने परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन के बाद एक और तिब्बती मठ पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। २० जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिबंधों में भिक्षुओं के घर की लगातार तलाशी और अनिवार्य दैनिक राजनीतिक विचारधारा सत्र शामिल हैं। इन कार्रवाइयों ने भिक्षुओं की पारंपरिक धार्मिक रिवाजों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे उनके आध्यात्मिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप पर व्यापक दुःख और आक्रोश फैल गया है। विशेष रूप से दलाई लामा के जन्मदिन के दौरान, खानाबदोश समुदायों द्वारा भिक्षुओं को अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करने की लंबे समय से चली आ रही रीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह रीति विशेष रूप से पांचवें और छठे तिब्बती महीनों में मनाई जाती है। भिक्षुओं को इन समुदायों का दौरा करने से रोक दिया गया था, जिससे भिक्षुओं और खानाबदोशों दोनों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं को कम किया गया।

आदरणीय शेरसांग ग्यात्सो का जन्म पारंपरिक अमदो प्रांत के माल्हो क्षेत्र (चीनी: हुआंगनान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर) के सोगजों काउंटी के अरिंग गांव में हुआ था। उन्होंने सांग मठ के पांच पारंपरिक महाविद्यालयों में से एक- ग्युपा महाविद्यालय में अध्ययन किया और वहां के हजारों भिक्षुओं के बीच एक उत्कृष्ट साधक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी शिक्षा और नैतिक निष्ठा की समान रूप से प्रशंसा की गई। सांग मठ स्वयं तीन प्रमुख क्षेत्रों- माल्हो (चीनी: हुआंगनान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर), त्सोल्हो (हैनान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर), और गोलोग (गुओलुओ तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर) के भिक्षुओं का आश्रय और साधना स्थल है।

तिब्बतियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर, विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन के आसपास, चीन की कार्रवाई उसके द्वारा तिब्बतियों के मौलिक अधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन को दर्शाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर निगरानी, हिरासत और धार्मिक रीति-रिवाजों पर प्रतिबंध शामिल हैं। चीनी अधिकारियों ने करजे के मठों में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को नजरबंद कर दिया, संगसोल धूपबत्ती जैसे पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया और तिब्बतियों को उनके परिवारों को बताए बिना हिरासत में ले लिया। कीर्ति सहित मठों पर छापे मारे गए, पूछताछ की गई और कीर्ति रिनपोछे जैसे मठ के पूजनीय नेताओं की तस्वीरें और शिक्षाएं रखने को 'राजनीतिक अपराध' घोषित करने की धमकियां दी गईं। धार्मिक समूहों को तोड़ दिया गया, सभाओं में केवल पांच भिक्षुओं के जाने की अनुमति दी गई और तिब्बतियों को निजी जन्मदिन समारोहों की तस्वीरें भी जमा करने के लिए मजबूर किया गया। ल्हासा और अन्य क्षेत्रों में सशस्त्र सुरक्षा बलों तैनाती ने तिब्बतियों के परम पावन दलाई लामा से संबंध तोड़ने और आस्था की अभिव्यक्ति को दबाने के चीनी सरकार के व्यापक अभियान को मजबूत किया। यह सब कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और यहां तक कि चीन के अपने संविधान का भी सीधा उल्लंघन है।

- सीटीए के डीआईआईआर में तिब्बत एडवोकेसी अनुभाग में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क द्वारा तैयार रिपोर्ट

◆ 15. तिब्बती राजनीतिक बंदी का परिचय

པལཅུང་། पालचुंग

गिरफ्तारी की तारीख: जुलाई २०२५

वर्तमान स्थिति: हिरासत में

आरोप: परम पावन दलाई लामा की स्तुति में गीत गाना

संक्षिप्त परिचय : न्गाबा के अदु गांव के एक युवा तिब्बती गायक पालचुंग को जुलाई २०२५ के शुरुआती हफ्तों में चीनी अधिकारियों ने जबरन हिरासत में ले लिया था। उनकी गिरफ्तारी तब हुई, जब उन्होंने परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन पर प्रसिद्ध गायक सुक्ते के साथ परम पावन की स्तुति में 'शांति का राजकुमार' मुखरे का एक गीत गाया। फिलहाल बार-बार चिंता जताए जाने के बावजूद पालचुंग का ठिकाना और उनकी स्थिति अज्ञात बनी हुई है, जिससे उनका परिवार गहरे सदमे में है। हालांकि पालचुंग कोई प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्ती नहीं हैं, फिर भी परम पावन के सम्मान में उनके गायन मात्र के लिए उन्हें कड़ी सजा दी गई है। उनकी नजरबंदी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे चीनी अधिकारी तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके आध्यात्मिक नेता के प्रति श्रद्धा को दबाने के लिए गिरफ्तारियों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। पालचुंग की शादी को तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं और वे तीन साल के एक बेटे के पिता हैं।

२३ अगस्त, २०२५



PROFILING TIBETAN POLITICAL PRISONERS

པལཅུང་།

PALCHUNG

Date of Arrest: July 2025
Current Status: Detention
Charges: Singing a Song in Praise of His Holiness the Dalai Lama

Brief Profile: Palchung, a young Tibetan singer from A'du Village in Ngaba, was forcibly detained by Chinese authorities in early weeks of July 2025. His arrest came after he performed a song titled "the Prince of Peace" in praise of His Holiness the Dalai Lama during the celebration of His Holiness's 90th birthday with renowned singer Tzoktre. Despite repeated concerns, Palchung's whereabouts and condition remain unknown, causing deep distress for his family. Palchung, while not a widely known public figure, yet his simple act of singing in honor of His Holiness has been met with severe punishment. His detention highlights how Chinese authorities continue to use arrests as a political tool to suppress Tibetans' cultural identity and reverence for their spiritual leader. Palchung has been married for over three years and is the father of a three-year-old son.

23 August 2025

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.

Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.

You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.

We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Coordinator

India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अमार व्यक्त करता हूँ कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदार भागीदारी रहा है।

तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परम्परागत दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।

आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नहीं रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहाँ से खाना हो चुका है।

इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे हैं। और आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी पुष्टी हमें तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीचे लिखे गये पता या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमें समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि

कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पता: भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच-10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर-03, नई दिल्ली-110024

फ़ोन: 011-29830578

ई-मेल: coordinator@indiatibet.net



: चीन ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह के दौरान तिब्बत में कड़े सुरक्षा उपाय किए और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया



: तिब्बत की नदी पर जल-युद्ध तेज करने की चीनी रणनीति



करुणा वर्ष में तिब्बती और कन्नड़ समुदाय द्वारा याद किए गए स्वर्गीय मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा